भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1102
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

'रामबाण' प्रयोगशाला

1102. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य डिलीवरी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वायरस का शीघ्र पता लगाने के लिए अस्पतालों के निकट स्माल बाउल शृंखला-प्रयोगशाला-3 और एसबीएस-3 प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहाँ 'रामबाण' नामक प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं;

(ङ) क्या महाराष्ट्र में स्वास्थ्य संस्थाओं के बाहर 'रामबाण' नामक रैपिड एक्शन मोबाइल लैब्स तैनात की गई हैं;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) महाराष्ट्र की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए ये मोबाइल लैब्स कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), जो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, इसके देश भर में 28 संस्थान हैं जिनमें अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं जोकि जैव-चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए कार्यरत हैं। आईसीएमआर एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान अनुदानों के माध्यम से 300 से अधिक चिकित्सा महाविद्यालयों और संस्थानों को सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यक्रम (एनएचआरपी) के अंतर्गत 12 चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 30 बड़ी बहु-राज्य परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है।

डीएचआर ने पूरे देश में वायरल अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) का नेटवर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसी 165 वीआरडीएल प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है।

वीआरडीएल योजना का प्राथमिक उद्देश्य नवीन अनुसंधान को सुगम बनाना, उच्च-गुणवत्ता वाली नैदानिक सेवाएँ प्रदान करना और जन स्वास्थ्य पेशेवरों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये प्रयोगशालाएँ समय पर निदान, वायरल रोगजनकों की पहचान, प्रकोप के दौरान संसाधनों के उपयोग में सहायता, वायरल रोगों पर आँकड़े तैयार करने और जन स्वास्थ्य नीतियों के संचार हेतु अनुसंधान करके स्वास्थ्य प्रणाली को सहयोग प्रदान करती हैं।

देश को जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ, स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकास हेतु प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, जम्मू, डिब्रूगढ़, जबलपुर और बेंगलुरु में चार क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) और नागपुर में राष्ट्रीय वन हेल्थ संस्थान (एनआईओएच) को आईसीएमआर के लिए अनुमोदित किया गया है। पुणे स्थित राष्ट्रीय ट्रांसलेशनल विषाणु विज्ञान एवं एड्स अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईटीवीएआर) के सैटेलाइट केंद्र को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, संक्रामक रोग अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं (आईआरडीएल) में उन्नयन हेतु 10 वायरल अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) को शामिल किया गया है, और **बायोसेफ्टी** लेवल 3 (बीएसएल-3) प्रयोगशालाओं में उन्नयन हेतु 5 वीआरडीएल को शामिल किया गया है।

आईसीएमआर ने बताया है कि उसने कोविड महामारी के प्रबंधन और उससे निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें 18 महीनों के भीतर प्रयोगशालाओं की क्षमता (1 से 3300 प्रयोगशालाएँ) बढ़ाना, स्वदेशी वैक्सीन, कोवैक्सिन का विकास, कोविशील्ड और कोवोवैक्स के नैदानिक परीक्षण; सभी प्रकार के कोविड डायग्नोस्टिक परीक्षणों का सत्यापन जिससे लागत में 50 गुना कमी आई; नैदानिक मार्गदर्शन और सलाह जारी करना, जीनोमिक अनुक्रमण करना, प्लाज्मा थेरेपी के लिए नैदानिक परीक्षण, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सॉलिडैरिटी ट्रायल में भाग लेना, जनसंख्या प्रतिरक्षा को समझने के लिए सीरो-सर्वेक्षण करना आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, आईसीएमआर ने विभिन्न संक्रामक बीमारियों के लिए स्वदेशी टीकों और उपचारों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने इन-विट्रो डायग्नोस्टिक (आईवीडी) उपकरणों, पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षण किटों और निगरानी उपकरणों के क्षेत्रीय सत्यापन में भी सहायता की है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने से जुड़े हैं।

(ख) से (च) : आईसीएमआर ने सूचित किया है कि पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत, रामबाण (रैपिड एक्शन मोबाइल बीएसएल-3+ एडवांस्ड ऑगमेंटेड नेटवर्क) नामक दो मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 (बीएसएल-3) वैन पहले ही खरीद ली गई हैं और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) पुणे और क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसी) गोरखपुर में तैनात की गई हैं। इन वैन को प्रकोप की जरूरतों के आधार पर किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2023 में निपाह वायरस के प्रकोप के दौरान, एक मोबाइल बीएसएल-3 वैन कोझीकोड में तैनात की गई थी, जहाँ इसने संदिग्ध नमूनों के परीक्षण की सुविधा प्रदान की थी। इसी प्रकार, जुलाई 2024 में, वैन को प्रकोप प्रतिक्रिया संबंधी गतिविधियों के लिए मलप्पुरम में तैनात किया गया था। मोबाइल प्रयोगशालाएँ वास्तविक

समय डेटा संग्रह में मदद करती हैं जो त्वरित नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं और किसी भी उभरने वाले वायरल संक्रमण के आगे प्रसार को रोकती हैं। इन मोबाइल प्रयोगशालाओं का उपयोग प्रयोगशाला संचालन और बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल में वैज्ञानिक और जैव चिकित्सा कर्मियों के व्यापक प्रशिक्षण के लिए भी किया गया है।

(छ): मोबाइल बीएसएल-3 प्रयोगशालाएँ अत्यधिक विशिष्ट प्रयोगशालाएँ हैं जिनकी लागत करोड़ों रुपये तक होती है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती, हालाँकि, महाराष्ट्र के एनआईवी पुणे में स्थित एक मोबाइल बीएसएल-3 प्रयोगशाला को प्रकोप के दौरान आवश्यकतानुसार कहीं भी तुरंत तैनात किया जा सकता है।

*****